सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-22 | 22 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

चुनाव आया, तो फिर अलापा राम मन्दिर का राग

पिछले लोकसभा चुनावों से पहले, देश के लोगों को नहीं पता था कि वास्तव में 'गुजरात मॉडल' क्या था। इसलिए, गुजरात में राम मंदिर, हिंदुत्व आदि के पुराने मुद्दों के रहते हुए भी नरेंद्र मोदी के उस ज्ञात-अज्ञात 'गुजरात मॉडल' को ही सारे रिकार्ड तोड़ प्रबलता के साथ देश भर में प्रचार दिया गया। कई लोगों ने सोचा कि जब मीडिया इतनी अच्छी तरह से कह रहे हैं, तो शायद यह अच्छा ही होगा। भारी प्रचार, पैसों और प्रशासन की बड़ी भारी मदद के बल पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। लेकिन जल्द ही यह पता चल गया कि गुजरात मॉडल अर्थव्यवस्था का एक जर्जर चेहरा है।

अप्रैल-मई 2019 में, लोकसभा चुनाव फिर आ रहे हैं। अब फिर, भ्रम बनाए रखने के लिए उसी 'गुजरात मॉडल' की बात यत्नपूर्वक पेश करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। क्योंकि वरना वह मॉडल नरेंद्र मोदी को परेशानी में डाल देगा। पिछले पांच सालों में बेरोजगारी की समस्या ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया है, फसलों के वाजिब दाम न मिल पाने से हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी उदासीनता से विभिन्न राज्यों में हजारों हजार किसान रोष व्यक्त करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं। जीएसटी के एक धक्के से छोटे व्यापारी तबाह हो गए हैं, नोटबंदी के तुगलकी फरमान की मार लोग अभी भी झेल रहे हैं। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजमर्रे की जरूरी चीजों की बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। व्यापम और राफेल जैसे आर्थिक घोटालों से, बड़े-बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों को बैंकों के पैसे मार लेने की छूट देने से और बैंको को दिवालिया बनाने जैसे काम करने से नरेंद्र मोदी की सरकार अत्यधिक बदनाम हो चुकी है। भाषणबाज नरेंद्र मोदी के भाषण भी अब लोगों को नहीं भाते हैं, बल्कि उनकी खिल्ली उड़ाने वाले के रूप में, नरेंद्र मोदी को उल्टे पड़ रहे हैं। एकाधिकार पूंजीपति घरानों के चरणों में नतमस्तक नरेंद्र मोदी सरकार के चरित्र का आज लोगों को पता चल चुका है। इसलिए, सत्ता में दोबारा लाने के लिए, 'राम मंदिर के उसी मुद्दे को फिर उठाओ'।

संघ परिवार और बीजेपी नेताओं द्वारा राम मंदिर के निर्माण का फिर से शोरगुल मचाने और संतों के साथ धर्म-संसद बिठाने की प्रक्रिया से भी यह साफ जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। 1989 से देश के लोग देखते आये हैं कि पिछले 30 सालों से जब-जब बीजेपी किसी संकट में पड़ती है, तभी बीजेपी की रामभक्ति उमड़ने लगती है।

1989 में रामशिला पूजन के नाम पर ईंटों की पूजा, 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा, 1992 में कारसेवा और बाबरी मस्जिद को तोड़ना आदि भाजपा-संघ परिवार के कारनामे थे। जनजीवन की समस्याओं को हल करने के लिए किसी आंदोलन के बजाय, संघ परिवार यह खेल खेल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन से जुड़े

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बीजेपी सरकार अंबानियों के स्वार्थ में तीन गुने दामों पर खरीद रही है विमान : राफेल घोटाला

फिर एक घोटाले में फंस गई है मोदी सरकार। अब उसकी हालत सांप के मुंह में छछुंदर वाली हो गई है। न निगलते बनता है और न उगलते। भाजपा से एकाधिकारी पूंजीपतियों की घनिष्ठता शुद्ध पारस्परिक हितों अर्थात् लेन-देन की सौदेबाजी की है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्रोनी कैपीटलिज्म कहते हैं, उसी का ताजा उदाहरण है राफेल युद्धक विमान की खरीद को लेकर हुआ महा घोटाला।

36 विमानों की खरीद को लेकर बीजेपी सरकार पर अनिल अंबानी को 21 हजार करोड़ रुपये के सौदे का एसाइनमेंट सौंपने का आरोप लगा है। 'भ्रष्टाचार नहीं हुआ है'–यह बात भी भाजपा नेता दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं, न ही यह स्वीकार करने का इन नेताओं में नैतिक बल है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री इस मामले में जितना बार-बार पलटी मार रहे हैं, अनिल अंबानी उतना ही गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं–मेरे नाम पर कुछ भी कहा, तो अच्छा नहीं होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे सरकार ने नहीं, बल्कि फ्रांसीसी कंपनी ने ही अनुबंध किया।

2012 में, यूपीए सरकार ने फ्रांसीसी सरकार के साथ दो इंजनों वाले बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार, फ्रांस की विमान निर्माता डेसॉल्ट कंपनी से राफेल नामक 126 लड़ाकू विमान खरीदने की बात हुई थी। कंपनी इनमें से 18 को तैयार हालत में देगी और बाकी 108 राष्ट्रीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ मिल कर डेसॉल्ट भारत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये जाएंगे।

लेकिन मोदी सरकार ने 2015 में हुए इस अनुबंध को रद्द कर दिया और एक और समझौता किया। अब 36 विमान खरीदने का फैसला किया गया है। समझौते के मुताबिक, सभी विमान फ्रांस में बनाये जाएंगे और कीमत 59 हजार करोड़ रुपये होगी। आरोप लगाया गया है कि पिछले समझौते में विमान पर लागत खर्च 526 करोड़ रुपये था, वहीं मौजूदा समझौते में हर विमान पर लागत खर्च 1670 करोड़ रुपये आएगा। इसके अलावा, इस समझौते में लड़ाकू विमानों को भारत में एचएएल के साथ संयुक्त रूप से निर्माण करके उन्नत तकनीक हासिल करने का जो मौका मिला था वह भी इस समझौते के द्वारा विसर्जित कर दिया गया। प्रधान मंत्री लंबे समय से 'मेक इन इंडिया' का ढोल पीटते आ रहे हैं, यह सौदा उनकी इस नीति के ही खिलाफ है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कौन सा कारण है कि प्रधान मंत्री अपनी घोषित नीति के खिलाफ जाकर फैसला ले रहे हैं, जहां आरोप यह लग रहा है कि नए अनुबंध में हर विमान के दाम पिछले अनुबंध की तुलना में तीन गुना अधिक पड़ रहे हैं?

यहां से उभर रहा है अंबानियों पर मेहरबानी करने का सवाल। नए समझौते के मुताबिक, विमान की खरीद पर कुल व्यय की आधी यानी लगभग 30 हजार करोड़ रुपये डेसॉल्ट कंपनी भारत के रक्षा क्षेत्र में विमान के अन्वेषण और उत्पादन के लिए निवेश करेगी। जैसा कि यह पता चला है, डेसाल्ट कंपनी ने 30 हजार करोड़ के सौदे के इस काम को करने के लिए जिन भारतीय कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें अनिल अंबानी की रिलायंस एरो

(शेष पृष्ठ 7 पर)

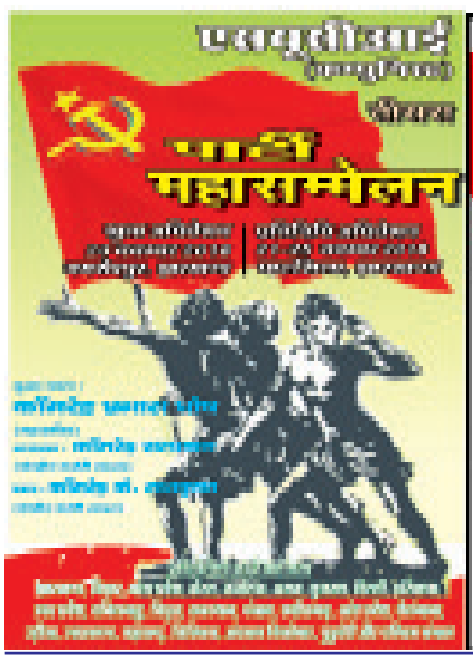

उड़ीसा में विशाल छात्र प्रदर्शन

भुवनेश्वर : छात्रों की ज्वलंत मांगों को बुलंद करते हुए सड़कों पर उतरे एआईडीएसओ कार्यकर्ता

भुवनेश्वर (उड़ीसा) : ग्रांट सिस्टम-सेमेस्टर-सीबीसीएस- हेकी- हेफा- एनएमसी-फीस वृद्धि-शिक्षा के साम्प्रदायीकरण आदि के खिलाफ 29 सितम्बर को एआईडीएसओ उड़ीसा राज्य कमेटी के आह्वान पर भुवनेश्वर में छात्रों का विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री और जन शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

चुनाव आया, तो फिर अलापा राम मन्दिर का राग ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुकदमे को तेजी से सुलझाने के लिए इस मामले को प्राथमिकता देने को कहा है। संघ परिवार का मानना है कि जनजीवन में कहर ढाहने वाली समस्याओं को हल करने की कोशिश करने के बजाय राम मंदिर की भावना और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर पाने से चुनावी फायदा उठाना ज्यादा आसान होगा। इसी आशा में संघ परिवार ने साम्प्रदायिकता का रंग देकर राम मन्दिर का शोरगुल मचाने की आसान राह ही चुनी। भूख से लोग मारे गए या नहीं, इलाज के बिना लोग तड़फ रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी की आग में जल रहे नौजवान छटपटा रहे हैं कि नहीं, महिलाओं की तस्करी, नारी देह-व्यापार, महिलाओं की इज्जत-आबरू पर हमले, यौन-उत्पीड़न महिलाओं पर अत्याचार उनके जीवन को असुरक्षित बना दे रहा है कि नहीं – ये सब सवाल लोग नहीं उठायेंगे यदि राम मन्दिर की भावना को भड़का दिया जाए – बीजेपी और संघ परिवार की यही साजिश है।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले को प्राथमिकताओं की सूची में नहीं रखते हुए कहा है कि अदालत की अपनी प्राथमिकताएं हैं। बात सुनने में जरूर अच्छी है। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या की इस भूमि को तीन हिस्सों में बांट कर दो तिहाई हिंदू पक्ष को और एक-तिहाई हिस्सा मुसलमान पक्ष में बांट देने को कहा था। इस फैसले से हिंदुत्ववादी पक्ष को अपार खुशी हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूरी भूमि पाने के लिए याचिका डाल दी थी। नतीजतन, न्यायपालिका भी ऐसे ही फैसले दे रही है ताकि हिंदुत्ववादी पक्ष या संघ परिवार नये सिरे से उग्र हिंदुत्व के हथियार को धार दे सके। आज, जब सुप्रीम कोर्ट प्राथमिकता के आधार पर मामला सुनने के लिए अनिच्छुक है, तो संघ परिवार के नेता एक तरफ जहां न्यायपालिका के प्रति हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, उनके द्वारा संचालित सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी कर मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं।

लेकिन कुछ सुबुद्धिसम्पन्न लोग शायद सोच रहे हैं और मीडिया यह भी प्रचार कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय की प्राथमिकताओं के आधार पर मामला नहीं सुनने के फैसले के नतीजतन या तो बीजेपी को बड़ी भारी अड़चन आई या बीजेपी को परेशानी हुई। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि वे संतों को इकट्ठा करके धर्म संसद बुलाने का निर्णय लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की वैसी ही कोशिश इस बार नहीं करेंगे जैसी पहले भी इन्हें करते सबने देखा था। इसलिए, जहां एक तरफ पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और कुछ महीने बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी तरफ, मोदी की छवि रसातल में है और 'गुजरात मॉडल' जैसा कोई चारा, झुनझुना या छलावा भी लोगों के हाथों में नहीं थमाया जा सकता है, तब राम मन्दिर का सहारा लेने के सिवा और किस का सहारा बीजेपी ले सकती है! इसलिए जिन संगठनों ने 1992 में ऐतिहासिक स्मारक बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने का घोर अन्याय किया, उनके उस अपराध की उन्हें सजा मिलने की बात थी, जिन्होंने न्यायपालिका की चरम उपेक्षा करके ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, अब उस अपराध के आरोपी संगठन न्यायपालिका से मांग करते हैं कि उन्हें राम मंदिर की भूमि दी जाए!

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नेताजी के किसी नीति-सिद्धांत को कभी किसी दिन माना ही नहीं, उन्होंने अचानक नेताजी का भक्त होने का दिखावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार नेताजी का आदर्श लोगों के सामने रखेगी।

नेताजी ने कहा था : "... भारत में हिंदू बहुमत में हैं, इसलिए 'हिंदू राज' की ध्वनि सुनाई दे रही है – ये सब आलसी विचार हैं। ... मेहनतकश लोग जिन समस्याओं से रूबरू हैं, क्या सांप्रदायिक संगठन उनकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकेंगे? बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, आदि समस्याएं कैसे हल होंगी – इस बारे में क्या उन्होंने कभी कोई भी मार्गदर्शन किया है?" लेकिन नरेंद्र मोदी की भाजपा बिल्कुल उल्टा ही काम कर रही है।

यह आज देश के सभी लोगों को बखूबी समझ लेना चाहिए कि मोदी सरकार जब अडानी-अंम्बानियों की ताबेदार के सिवा और कुछ नहीं है, तब लोगों में फूट डालने के लिए वे हिंदू-मुस्लिम दंगा कराने के लिए ही इस मुद्दे को इस्तेमाल करेंगें और राम मन्दिर के नाम पर साम्प्रदायिक फूट डालने और उसके आधार पर चुनावी फायदा उठाने की उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए लोगों की आगे आना चाहिए।

किसानों ने सौंपा ज्ञापन

अमरोहा (उत्तर प्रदेश) : थाना नौगांवा सादात पर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस द्वारा अकारण लाठीचार्ज किये जाने के विरोध में और नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा जिले में शामिल करने आदि मांगों के संबंध में 11 अक्टूबर को एआईकेकेएमएस की ओर से जिला अधिकारी, जनपद अमरोहा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन में काफी लोग शामिल थे। 9 अक्टूबर को किसानों द्वारा थाने के समक्ष हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। अचानक पुलिस ने उन पर देर शाम लाठीचार्ज कर दिया था और उनका तंबू फाड़कर उखाड़ फेंक दिया था। संगठन द्वारा इस घटना पर गहरा रोष प्रकट करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। किसान क्रांति यात्रा पर दिल्ली में किए गए लाठीचार्ज की भी घोर निंदा की गई। एआईकेकेएमएस ने मांग की कि चीनी मिलों को तुरंत चालू किया जाए।

ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र सिंह, अमर सिंह, गंभीर सिंह, धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह, अकबर, असद अली, वाहिद खान, महबूब अली, दिगराज सिंह, अनिल कुमार, नासिर खान, अनीस अहमद, हरप्रसाद, छोटे सिंह, पवन आदि कई लोग शामिल थे।

अमरोहा में विरोध प्रदर्शन करते हुए एआईकेकेएमएस कार्यकर्ता

जन समस्याओं को लेकर दिया धरना

गुना (मध्यप्रदेश) : बिजली के बढ़ते दामों, गुना जिले के 500 सरकारी स्कूलों को बन्द करने, राशन की दुकानों की अव्यवस्था, किसान-विरोधी नीतियों, के खिलाफ एसयूसीआई(सी) की जिला कमेटी द्वारा 29 अगस्त को स्थानीय हनुमान चौराहे पर जिला स्तरीय धरना देकर विरोध जताया गया। धरने की शुरुआत 'काले कानूनों का राज अब नहीं चलेगा' गीत के साथ हुई।

धरने को सम्बोधित करते हुए कॉ. लोकेश शर्मा ने कहा कि आम जानता के प्रति शासन-प्रशासन के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये व जनविरोधी नीतियों के कारण गुना जिले की जनता त्रस्त है। बिजली के बढ़े हुए बिल देखकर लोगों को झटका लगता है। समाज का हर तबका परेशान है। ऐसी एक स्थिति में इन तमाम समस्याओं के खिलाफ संगठित जन आन्दोलन ही एकमात्र विकल्प है।

धरने को शहर के प्रबुद्ध नागरिक राकेश मिश्रा, नरेंद्र भदौरिया आदि ने भी समर्थन दिया शहर के अलग-अलग क्षेत्रों, गावों से सैकड़ों की संख्या में आम लोग शामिल हुए। धरने का संचालन संगीता आर.बी. ने किया।

धरने के उपरांत संजीव कुमार के नेतृत्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया जिसमें गुना शहर की गलियों मे पर्याप्त रोशनी मुहेया कराने, सड़कों की मरम्मत कराई जाने, डी.डी.टी. छिड़काव कराने आदि की माँग को प्रमुखता से उठाया गया। इसके पश्चात बिजली के प्रति यूनिट दर को कम किया जाए, बिजली बिलों में पारदर्शिता लाई जाए व औसत खपत, आकलित खपत के नाम पर मनमानी वसूली पर रोक लगाई जाए की माँग को लेकर एडवोकेट सीमा राय के नेतृत्व में विद्युत विभाग में ज्ञापन दिया गया। अन्त में कॉ. लोकेश शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि शहर में 500 सरकारी स्कूलों को बन्द करने का निर्णय अविलम्ब वापिस लिया जाए, शराबबन्दी लागू की जाए तथा शहर के रिहायशी इलाकों से शराब के ठेके हटाये जाएं, किसानों की उपज का वाजिब दाम मिलने सुनिश्चित किए जाएं एवं किसानों के सभी कर्जे माफ किये जाएं; खाद, बीज, डीजल, बिजली आदि खेती के सभी जरूरी सामानों पर पर्याप्त सब्सिडी दी जाए तथा खेती की लागत को कम किया जाए।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तत्काल बिना शर्त रिहा करो

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केन्द्रीय कमेटी का बयान

देश के विभिन्न हिस्सों के वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की छापे और गिरफ्तारी के संबंध में एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 27 अगस्त 2018 को प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया :

बीजेपी के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन द्वारा भीमा-कोरेगांव घटना से उनके जुड़े होने के आरोप में वरिष्ठ मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों पर घोर गैर-लोकतांत्रिक ढंग से छापे मारना और उन्हें गिरफ्तार करना असहमती की आवाज उठाने वालों का गला घोंटने का और विरोध करने वाले लोगों में डर-भय पैदा करने का एक फासीवादी कदम है जो अत्यधिक निंदनीय है। हम उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग करते हैं।

एआईडीएसओ के बैनर तले छात्र प्रदर्शन

तिरुपति (आंध्रप्रदेश) : आंध्रप्रदेश के तिरुपति में डिग्री छात्रों की समस्याओं पर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्टस् ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने 27 अगस्त को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन तक एक रैली आयोजित की और रेक्टर प्रोफेसर जी. जानकी रामय्या को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि परीक्षा शुल्क और पुनर्मूल्यांकन शुल्क तत्काल कम करें। मूल्यांकन में अनियमितताओं को रोकें और परिणाम समय पर जारी किए जाने चाहिएं। डिग्री अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित की जाए। डिग्री स्तर पर सेमिस्टर सिस्टम वापस लिया जाए

रेप, गैंगरेप और देह व्यापार के आरोपों के मद्देनजर 'शेल्टर होमों' के कार्य संचालन की जांच के लिए उच्च शक्तिप्राप्त समिति बिठाने के लिए

कॉमरेड प्रभास घोष ने लिखा प्रधान मंत्री को पत्र

भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी,

हम देश में महिलाओं पर अपराधों के बढ़ने पर गहरे चिंतित हैं। बलात्कार? सामूहिक बलात्कार, बलात्कार पीड़ितों, की क्रूर हत्याओं, दहेज के कारण होने वाली मौतों, ऑनर किलिंग और महिलाओं पर ऐसे अन्य क्रूर हमलों ने वास्तव में खतरनाक रूप धारण कर लिया है जो यह दर्शा रहा है कि स्वतंत्र भारत में महिलाएं कितनी असुरक्षित और अरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 106 महिलाओं से बलात्कार किया जाता है। भारत सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में 42% लड़कियों का यौन शोषण किया गया है और नाबालिग लड़कियों के बलात्कार में 82% की वृद्धि हुई है। एक चौंकाने वाला वीडियो जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया कि एक किशोर लड़की को उत्तर प्रदेश में युवा लड़कों के एक समूह द्वारा खींचा जा रहा है और छेड़छाड़ की जा रही है। इससे पहले, बिहार में इसी तरह की घटना में आठ लड़कों के एक समूह द्वारा एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, खींचना-घसीटना और निर्वस्त्र करने की कोशिश करते देखा गया। सबसे अधिक अमानवीय बात यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण लड़कियों को अक्सर बलात्कारियों द्वारा अपनी पाशविक वासना को तृप्त करने के लिए निशाना बनाया जाता है।

पिछले साल, देश ने फिर एक और क्रूर बलात्कार की घटना देखी, जो आधुनिक दुनिया में मुसीबत ढाहने वाले सभी अपराधों में से अत्यंत घृणास्पद अपराध है और अपराध से भी ज्यादा घृणित कृत्य है, वह है इस बहशियाना कुकर्म को करने वालों को सरकार-प्रशासन की ओर से ढाल बनकर बचाना। उन्नाव में मक्खी गांव की एक 17 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि जब वह एक नौकरी की तलाश में गई, तो उसे अगवा कर लिया गया और एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और उसके भाई सहित उसके सहयोगियों द्वारा एक हफ्ते से ज्यादा समय तक उससे गैंगरेप किया गया। पीड़िता द्वारा आरोपी का नाम लिये जाने के बावजूद, उसे हिरासत में नहीं लिया गया। इसके बजाय, वह इतना बेखौफ हो गया कि जीवित पीड़िता के परिवार को बुरे अंजाम भुगतने की लगातार धमकी देता रहा। न्याय के एक विचित्र मोड़ में, पुलिस ने जीवित पीड़िता के पिता को गैर-कानूनी तौर पर असलाह (आग्नेयास्त्र) रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद, आधिकारिक कथनानुसार, जीवित पीड़िता के पिता की उसके हाथों, जांघों, नितंबों, घुटनों और पेट के आस-पास कई चोटों और घर्षण के बावजूद 'बड़ी आंत के छिद्रण के कारण रक्त विषाक्तता' के कारण पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। एक मुख्य आरोपी, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन यह महिलाओं के खिलाफ नरसंहारक कृत्यों का अंत नहीं था।

गत जनवरी में जम्मू क्षेत्र में कठुआ में आठ वर्षीय लड़की से बलात्कार, अंग-भंग और हत्या को मानव की पाशविकता का एक ऐसा कृत्य माना जाएगा जिसने हम सभी को शर्मशार कर दिया है। बलात्कार को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करना तो और भी शर्म की बात थी। आश्चर्य की बात यह है कि कसूरवार सांप्रदायिक लाइन वालों के लिए एक नृशंस बलात्कार ऐसे पूरी तरह से खुला क्रीड़ांगन कैसे हो सका। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस अपहरण, निर्दयीकरण, कई बार बलात्कार और अंत में हत्या के चश्मदीद गवाहों को आरोपियों के परिजनों और दोस्तों द्वारा धमकी दी जा रही है। जम्मू-कश्मीर में कठुआ में और उत्तर प्रदेश में उन्नाव में मासूम लड़कियों से वीभत्स बलात्कार होते हुए भी समाज के विभिन्न तबकों की ओर से बड़े हिंसक व अन्यायपूर्ण आचरण किये जाने का सबब बन जाने, बलात्कारियों या बलात्कार के आरोपियों की ढाल बनकर उनके बचाव में कुछ लोगों के आ जाने और सत्ताधारियों के पक्षधर बन जाने से लगता है कि यह मध्ययुगीन कूड़ा-करकट अभी बचा हुआ है। देश को यह भी पता चला है कि कैसे स्वयंभू धार्मिक गुरु लड़कियों की इज्जत-आबरू को लूटते हैं और अपने आश्रमों में इस या उस बहाने जब चाहे उनसे बलात्कार करते हैं। अगर कुछ पीड़िताओं ने इन अपराधों को उजागर करने का दुर्लभ साहस नहीं दिखाया होता, तो ये निरंतर यूं ही होते रहते और हमेशा के लिए दबे रहते। इन लड़कियों के बयान से भयानक विवरण सामने आए हैं, जिसके अनुसार पीड़िताओं से न केवल दिन पर दिन छेड़छाड़ की, बल्कि इसके अलावा इन स्वयंभू भगवानों ने पीड़िताओं को ''धमकी भी दी'' कि विरोध करने की कोशिश की या मुंह खोला तो उनको और उनके माता-पिता को भी जान से मार देंगे। इसने केवल यही दिखाया कि 2012 के निर्भया कांड के बाद भी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और सरकार-प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ती न होने देने के लिए सभी निवारक उपायों को अपनाने का वादा किया था, ठोस काम कुछ भी नहीं हुआ है और स्थिति को और भी खराब होने दिया गया है।

जहां देश के राजधानी शहर में हुई त्रासदी राष्ट्रव्यापी सदमे और भय के तौर पर नजर आई थी, वहीं बिहार के बैकवाटरों में जो अपराध हाल ही में हुआ है, वह तो और अधिक भयानक है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की देखरेख में, एनजीओ द्वारा संचालित 'होम' (आश्रयस्थल) में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। सबसे डरावनी बात यह है कि लड़कियों में से एक, जो यौन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए पर्याप्त दिलेर थी, को गिरफ्तार कर लिया गया और मार कर कंपलैक्स के अंदर दफना दिया गया, एक घृणास्पद वारदात है जिसकी पुष्टि जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी की है। पुलिस का कहना है कि लड़कियों से बलात्कार करने से पहले उन्हें नशा कराने के लिए मिर्गी के लिए दवाइयों सहित 67 नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। यह सवाल उठता है कि अपराध को दबाकर क्यों रखा गया। क्या हुआ था इसके बारे में क्या विभाग को पता था? संदेह गहरा हो जाना चाहिए क्योंकि ''आश्रय'' का स्वामित्व स्थानीय राजनेता के पास है, जिसके पास कुछ स्थानीय समाचार पत्रों का स्वामित्व भी है और उसके द्वारा अपने रसूखों का इस्तेमाल अपने एनजीओ के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से, पांच साल पहले मुजफ्फरपुर के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद उसकी परियोजनाओं को क्लीयरेन्स के रूप में उसके प्रति बार-बार दानवीरता दिखाई गई और मंजूरी दे दी गई थी और उसके 5 शेल्टर (आश्रय) चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान दिया गया। अगर एक निजी अकादमिक इकाई द्वारा तैयार की गई सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं आई होती, तो इस कांड से अभी तक भी पर्दा नहीं उठतां। यह पता चला है कि घर का मालिक और इस अपराध के मुख्य आरोपी शायद इस तरह की और भी वंचनाओं और अकल्पनीय क्रूरता में संलिप्त हो सकता है। मुजफ्फरपुर रेड लाइट क्षेत्र में उसी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे एक और घर से 11 महिलाएं और 4 बच्चे पुलिस को गायब मिले हैं।

बिहार के इस 'आश्रय घर' का पर्दाफाश होने के साथ ही साथ, यह प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में एक और 'आश्रय घर' की बाशिंदा लड़कियों पर भी इसी तरह के अत्याचार हो रहे थे। वहां रहने वाली लड़कियों को यौन दासी के रूप में इस्तेमाल करने की गाथा केवल एक नाबालिग लड़की के 'आश्रय घर' से बच कर भाग जाने के बाद प्रकाश में आई और पुलिस को बताया कि रात को लड़कियों को देह व्यापार के लिए ले जाया जाता था और सुबह लौटाया जाता था। इस 'आश्रय घर' में 42 लड़कियां थीं लेकिन केवल 24 को बचाया जा सका। अन्य 18 लड़कियां अभी भी लापता हैं। इसके कामकाज में अनियमितताएं पायी जाने पर सीबीआई जांच के बाद 2007 में आश्रय घर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लेकिन अधिकारियों ने जैसा कि दावा किया है कि, अदालत से स्टे आर्डर प्राप्त करने के बाद यह काम करना जारी है। लेकिन यूपी महिला और बाल कल्याण मंत्री ने स्वयं पुष्टि की कि देवरिया आश्रय घर अवैध रूप से चल रहा था। वहां रहने वाली लड़कियों को स्थानांतरित करने के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था, लेकिन यह आदेश लागू नहीं किया गया। आश्रय घर का लाइसेंस रद्द होने के बावजूद, स्थानीय पुलिस ने लड़कियों को भेजना जारी रखा।

लेकिन ये केवल हिमशैल की मात्र ऊपरी सिरा हैं। कौन जानता है कि देश में 9,000 के आसपास 'बाल आश्रय' और सरकार द्वारा वित्त पोषित मानसिक रोगियों के शरणस्थलों में क्या चल रहा है।

बिहार और यूपी दोनों जहां 'डरावने घरों' का पर्दाफाश प्रशासनिक सूचकांक पर खराब प्रदर्शन की ओर संकेत करता है। यह भी स्पष्ट है कि इनमें से अधिकतर संगीन अपराधों के आरोपी या तो 'राजनीतिक बाहुबली' हैं जो अदण्डित रहने का आनंद लेने के लिए सत्तारूढ़ हलकों में काफी रसूख रखते हैं या फिर सत्ता में बैठी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि विधायक हैं इसलिए किसी भी दंडकारी कार्रवाई से बचे रहते हैं। हालांकि इन आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल मुकदमा चलाने की जरूरत थी और कड़ा और अनुकरणीय दंड देना चाहए था, इस दिशा में कोई पहल नहीं होना यह दर्शाता है कि महिलाओं पर अपराध में या तो पुलिस-प्रशासन संलिप्त होता है या उसके साथ मिलकर अपराध हो रहा है।

इसलिए, हमारी राय है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायविदों, सामाजिक वैज्ञानिकों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं और प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेकर उच्च अधिकारप्राप्त समिति तत्परता से गठित की जानी चाहिए और किसी भी सरकार या प्रशासन के हस्तक्षेप से मुक्त 'आश्रयों', 'घरों' और 'शरणालयों' के कामकाज की देखरेख का जिम्मा देना चाहिए और चिंतित देशवासियों को वास्तविक स्थिति से वाकिफ कराने के लिए वास्तविक स्थिति की सच्ची रिपोर्ट सौंपनी चाहिएं। समिति को यह भी सलाह दी जा सकती है कि समस्या को सुलझाने की ठोस कार्रवाइयों का सुझाव दे जिन पर सरकार एक समयावधि के भीतर अमल कर सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे घरों में रहने वालियों से आइन्दा कोई दुर्व्यवहार, गलत इस्तेमाल या यौन उत्पीड़न न हो। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधान मंत्री के रूप में, आप हमारे सुझाव का अनुपालन करने की आवश्यकता की सराहना करेंगे और तदनुसार आगे बढ़ेंगे।

आपका

हस्ताक्षर / प्रभास घोष

महासचिव,

सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट)

दिनांक : 14 अगस्त 2018

बलात्कार की घटना के खिलाफ महिला संगठन ने ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली : स्थानीय गोल मार्किट स्थित एनडीएमसी के स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ 8 अगस्त को हुई बलात्कार की घटना के खिलाफ एआईएमएसएस की ओर से 13 अगस्त को उप राज्यपाल, नई दिल्ली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. सुबोध शर्मा और सचिव कॉ. रितु कौशिक भी शामिल थी। ज्ञापन में उनका ध्यान देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों पर बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं की ओर दिलाया गया। हालांकि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर चिंता का विषय यह है कि छात्राओं के लिए सुरक्षित स्थान माने जाने वाले स्कूल भी आज उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे। कुछ समय पहले भी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी थी। समाज में घट रही इस तरह की घटनाओं ने पूरे जन मानस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है? क्या हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं?

एक तरफ तो केंद्र व राज्य सरकारें महिलाओं व बच्चियों को सुरक्षा देने का ढिंढ़ोरा पीटती आई हैं, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देते नही थकती हैं, वहीं पूरे देश में एक के बाद एक बलात्कार जैसी हो रही शर्मनाक घटनाओं ने इनके इन नारों की पोल खोल दी है।

एआईएमएसएस ने महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध व बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने, विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा देने, गोल मार्किट स्थित एनडीएमसी स्कूल प्रशासन पर जाँच कमिटी गठित करने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने, जस्टिस वर्मा कमिटी की शिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने और नशाखोरी व अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग की।

तीसरी पार्टी कांग्रेस से पहले राज्य सम्मेलन सम्पन्न

हमारी पार्टी एसयूसीआई (सी) की तीसरी कांग्रेस से पहले विभिन्न राज्यों में राज्य सम्मेलन सम्पन्न हुए। इनके सत्र शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुए। सम्मेलन स्थल पर लाल झण्डा भी फहराया गया। सत्र की शुरुआत में इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी विचारक और पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उन पर रचित गीत गाया गया। प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर थीसिसों के साथ-साथ राज्य की संगठनात्मक रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। अंतर्राष्ट्रीय गान के साथ सम्मेलनों का समापन हुआ।

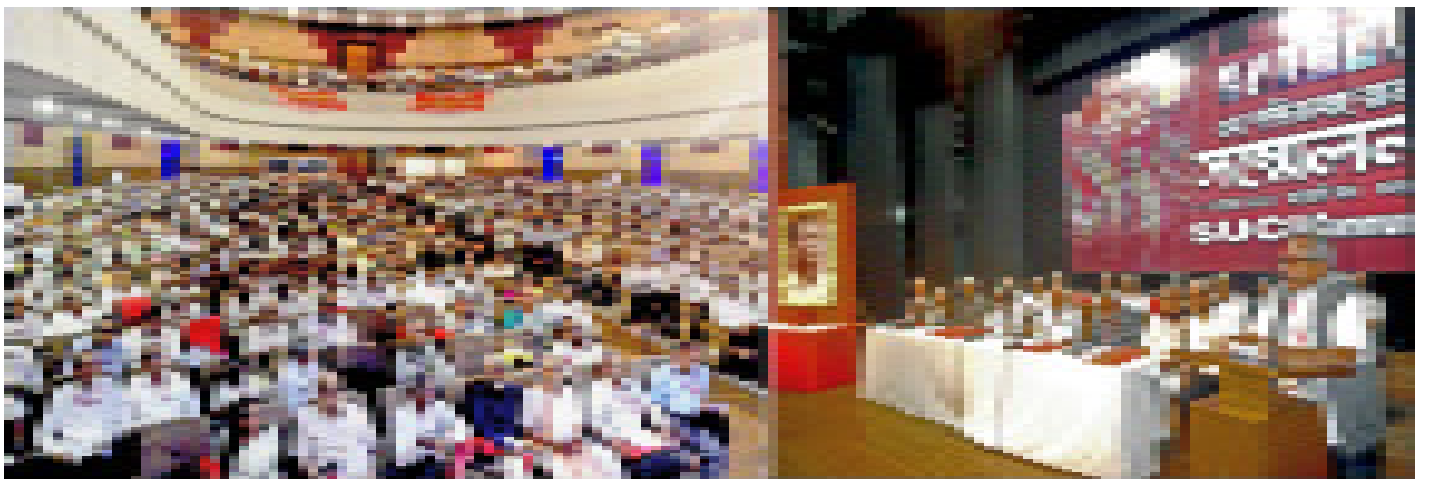

कोलकाता (प.ब.) पार्टी के पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु

पश्चिम बंगाल

एसयूसीआई (सी) पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन कोलकाता के महाजाति सदन में 2-3 नवंबर को आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों से कुल 798 प्रतिनिधि और 85 पर्यवेक्षक मौजूद थे।

केंद्रीय कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के रूप में मौजूद थे केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान, केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण, आसाम राज्य सचिव कॉमरेड चन्द्रलेखा दास और आसाम राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड सूरतजामान। सम्मेलन के संचालन के लिए कॉमरेड ध्रुवज्योति मुखोपाध्याय को अध्यक्ष और कॉमरेड सदानंद बागल, कॉमरेड चित्तरंजन चक्रवर्ती को सदस्य के रूप में लेकर एक अध्यक्षमण्डल का गठन किया गया। प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रस्तुत दस्तावेजों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में भाग लिया। उनके द्वारा दिए गए संशोधन और संयोजन स्वीकार किए गए। 21 से 25 नवम्बर तक घाटशिला में होने जा रही तीसरी पार्टी कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल के 298 प्रतिनिधि और 61 पर्यवेक्षकों सम्मेलन में चुने गए।

सम्मेलन ने 65 सदस्यीय राज्य कमेटी चुनी जिसके सचिव कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य चुने गए। सम्मेलन के अंत में, नई राज्य समिति की एक बैठक में 18 सदस्यीय राज्य सचिवमण्डल गठित किया गया। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु ने अपने भाषण में इस बार की पार्टी कांग्रेस के लक्ष्य-उद्देश्य याद दिलाते हुए इस महान जिम्मेदारी के लायक बनने का संघर्ष तेज करने के लिए प्रतिनिधियों के जरिए राज्य के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

राजस्थान राज्य कन्वेन्शन

पार्टी का राजस्थन राज्य कन्वेन्शन 11 नवम्बर को जयपुर में सम्पन्न हुआ। सबसे पहले पार्टी का झण्डा फहराया गया। शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत गाया गया। कन्वेन्शन की कार्रवाई पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड सत्यवान, पार्टी के स्टाफ मेम्बर कॉमरेड स्वप्न चटर्जी और बंगाल राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रतिभा नायक की देखरेख में हुई। कन्वेन्शन में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्थिति पर थीसिसों पर चर्चा हुई और आय-व्यय के विवरण सहित राज्य की राजनैतिक-सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। उपरोक्त तीनों नेताओं ने बात रखी। कन्वेन्शन में छह सदस्यीय सांगठनिक कमेटी बनाई गई और आगामी तीसरे पार्टी महासम्मेलन के लिए आब्जर्वरों का चयन किया गया। अन्तरराष्ट्रीय गान के साथ कन्वेन्शन का समापन हुआ।

पुडुचेरी राज्य सम्मेलन

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की अखिल भारतीय तीसरी पार्टी कांग्रेस के संबंध में पार्टी के पुडुचेरी राज्य स्तरीय प्रथम सम्मेलन का खुला सत्र राज्य तैयारी समिति के सचिव कॉमरेड लेनिनदुरई की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर 2018 को पुडुचेरी में आयोजित हुआ।

पार्टी के तमिलनाडु राज्य सचिव कॉमरेड ए. रंगास्वामी ने अपने उद्घाटन भाषण में दिखाया कि कैसे भारत में लेनिनवादी पार्टी संगठन के सिद्धांत पर आधारित सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई (सी) के गठन में कॉमरेड शिवदास घोष ने कड़ा संघर्ष किया, भारत में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की सही मूल राजनैतिक लाइन दी और विशेष रूप से सर्वहारा संस्कृति के क्षेत्र में कॉमरेड शिवदास घोष ने नया योगदान किया।

एसपीसी के सदस्य और एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड यू. मुथू ने कराइकल से पार्टी के सदस्य कॉमरेड अशोकन के अचानक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पुडुचेरी राज्य की तैयारी कमेटी के संयोजक कॉ. अनवराथन ने दिखाया कि शिक्षा की कमी या अनपढ़ता, बेरोजगारी की समस्या का कारण न तो जाति है, न धर्म है और न ही राष्ट्रीयता बल्कि इसका कारण पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में निहित है।

जयपुर (राजस्थान) : पार्टी के राजस्थान राज्य कन्वेन्शन का एक दृश्य

पार्टी के पुडुचेरी राज्य कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड के. श्रीधर

पार्टी के केंद्रीय स्टाफ कॉमरेड के. श्रीधर ने प्रदूषित व्यक्तिवाद की बजाय सामूहिक ज्ञान, सामूहिक अध्ययन, विचारों के सामूहिक आदान-प्रदान, सामूहिक तौर पर फैसला लेने, कार्य करने के सामूहिक तरीके, सामूहिक समीक्षा और सामूहिक जीवन अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह न केवल सर्वहारा क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि पूंजीवादी निजी संपत्ति और निजी संपत्ति जनित मानसिकता के विपरीत उच्च मानवीय मूल्यों के आधार पर एक नया समाज बनाने के लिए भी एक अजेय हथियार है।

प्रतिनिधि सत्र में एसपीसी सदस्यों कॉमरेड यू. मुथू, कॉमरेड आर. पांडियन और कॉमरेड ए. मोहम्मद बिलाल को लेकर बने अध्यक्ष मण्डल की देखरेख में कन्वेन्शन की कार्रवाई चलाई गई। राजनीतिक सांगठनिक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति पर ड्राफ्ट थीसिसें पेश की गईं। इन पर चर्चा-बहस में कॉमरेडों ने जोश-खरोश से भाग लिया।

सत्र के बीच कॉमरेड चिन्नाथंबी द्वारा रचित और गाए गए प्रगतिशील गीत भी प्रस्तुत किए गए।

पार्टी के स्टाफ सदस्य और मुख्य अतिथि कॉमरेड श्रीधर ने केन्द्रीय समिति द्वारा मनोनीत नई राज्य तैयारी कमेटी की घोषणा की।

महान नवम्बर क्रान्ति की सालगिरह पर जनसभा

रोहतक (हरियाणा) : महान नवंबर क्रांति के 101 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 11 नवंबर को रोहतक में एसयूसीआई(सी) की ओर से जनसभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य कॉ. जयकरण व रोहतक जिला सचिव कॉ. हरीश कुमार ने रूस की महान नवंबर क्रांति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रूस में महान समाजवादी क्रांति महान लेनिन के नेतृत्व में नवम्बर 1917 में सफल हुई थी।

जनसभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड अनूप सिंह ने की।

रोहतक में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. अनूप सिंह

किसानों ने ज्ञापन सौंपा

भिवानी (हरियाणा) : किसानों की मांगों पर ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन ने 24 सितम्बर को धरना दिया और एसडीएम, तोशाम की मार्फत ज्ञापन दिया। संगठन के जिला प्रधान कॉ. जिले सिंह ने बताया कि अज्ञात बीमारी व भारी बारिश से कपास व अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कपास की फसल काली पड़ कर बर्बाद हो गयी है। संगठन ने सरकार से मांग की कि किसानों की जायज मांगों पर सरकार तुरंत विचार करे व राहत दे।

जिला सचिव कॉ. रोहताश सिंह सैनी ने कपास व अन्य फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने और प्रभावित किसानों को 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने, गरीब किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करने, नहरों के अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी पहुँचाने, किसानों को डीजल आधे रेट पर देने, आवारा पशुओं का प्रबंध करने की मांग की।

ज्ञापन देने वालों में उदयबीर धारवानबास, रामनिवास आलमपुर, फूल सिंह दुल्हेड़ी, सुखबीर, बलबीर धारण, नरसिंह बागनवाला प्रमुख थे।

त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा मई दिवस को छुट्टियों की सूची से निकाले जाने का एआईयूटीयूसी ने किया विरोध

7 नवंबर 2018 को ऑल इंडिया यूनाइटिड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कामरेड शंकर साहा ने त्रिपुरा सरकार द्वारा मई दिवस की छुट्टी समाप्त करने के खिलाफ निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया :

यह सर्वविदित है कि मई दिवस -अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकजुटता दिवस, 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है। 8 घंटे के कार्य दिवस का मौलिक अधिकार हासिल करने के मजदूरों के ऐतिहासिक संघर्ष ने उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरंतर काम करने के बर्बर नियम से मुक्त कर दिया था। भारत भी इसका कोई अपवाद नहीं था। मई दिवस का महत्व किसी राज्य या देश की सीमा तक सीमित नहीं है। अत: मई दिवस का गौरवपूर्ण संघर्ष पूरी दुनिया में मजदूरों के 8 घंटे के कार्य दिवस के अधिकार को लागू करने, उनकी मान-मर्यादा और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है।

त्रिपुरा राज्य में बीजेपी-नीत सरकार के सत्तासीन होते ही बीजेपी समर्थित उपद्रवी तत्वों ने लेनिन जैसी महान विभूति व अन्यों के बुत तोड़ दिये। अपने कुकृत्यों की निरन्तरता में बीजेपी-नीत सरकार ने 2019 से लागू होने वाली छुट्टियों की सूची से मई दिवस को निकाल दिया है। हमारा दृढ़ मत है कि बीजेपी के उपरोक्त घृणित कृत्यों ने एक बार फिर उसके फासीवादी चेहरे को बेनकाब कर दिया है।

ऐसे मजदूर-विरोधी कदम की हम अपने संगठन एआईयूटीयूसी की ओर से घोर निंदा करते हैं। साथ ही हम जनवाद पसंद लोगों और आम मजदूरों का आह्वान करते हैं कि वे धर्म संप्रदाय व जाति के भेदभाव भूल कर प्रतिवाद की संयुक्त आवाज बुलंद करें और संयुक्त आंदोलन के बल पर राज्य सरकार को मजबूर कर दें कि वह फैसले को बदल कर मई दिवस को सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों की सूची में शामिल करे।

बाजरे की खरीद में आ रही परेशानियों बारे एआईकेकेएमएस ने ज्ञापन सौंपा

भिवानी (हरियाणा) : 18 अक्तूबर को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की जिला कमेटी के प्रधान जिले सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीसी, भिवानी से मिला। संगठन ने बाजरे की खरीद में आ रही भारी परेशानी और जुई मंडी में बाजरे की खरीद तुरंत चालू करने के बारे में डीसी भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

किसान संगठन के जिला सचिव रोहताश सिंह सैनी ने बताया कि बाजरा बेचने में ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी नहीं होने के कारण और सरकार की नाजायज शर्तों के चलते किसानों को जगह-जगह भटकना पड़ रहा है। उन्हें अपनी फसल ओने-पौने दामों में व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहले ही कपास व ग्वार की फसल अज्ञात बीमारी व अति वृष्टि के कारण नष्ट हो जाने से किसान काफी घाटे में हैं। किसान संगठन ने सरकार से मांग की कि बाजरे की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाए। बाजरे की सरकारी खरीद पर लगाई

भिवानी में ज्ञापन देते हुए किसान नेता

गई सभी नाजायज शर्तें तुरंत हटाई जाएं। जूई मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद तुरंत चालू की जाए और बीमारी व अति वृष्टि से खराब हुई फसलों का तुरंत रु.30,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएं। किसानों को डीजल आधे रेट पर दिया जाए। आवारा पशुओं का प्रबंध किया जाए। खेती में हर प्रकार की सब्सिडी बहाल की जाए।

प्रतिनिधिमंडल में सुखबीर ढाणी माहू, उदयवीर धारवानवास, फूल सिंह दुल्हेड़ी व राजकुमार दिनोद भी शामिल थे।

एआईयूटीयूसी से जुड़े निर्माण कर्मियों ने किया रोष प्रदर्शन

सोनीपत (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के बैनर तले मजदूरों ने 18 सितंबर को स्थानीय अंबेडकर पार्क से लघु सचिवालय तक रोष जुलूस निकाला। जुलूस गीता भवन चौक, शनि मंदिर, छोटू राम चौक से होते हुए लघु सचिवालय पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया।

एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. हरि प्रकाश ने कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने, भवन निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करने, कन्यादान के हित लाभ देने में विवाह पंजीकरण की शर्त हटाने, 5000 रुपये मासिक पेंशन देने और ऑनलाइन की वेबसाइट को चालू करने आदि की बार-बार मांग की है लेकिन

सोनीपत में मांगों के लिए सड़कों पर उतरे भवन निर्माण श्रमिक

सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने निर्माण श्रमिकों को सभी सुविधाएं देने की मांग की। भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के नेता कॉ. बलबीर सिंह, जिला प्रधान कॉ. रामफल जांगड़ा, एआईटीयूसी के जिला सचिव कॉ. बलवान सिंह और श्रमिक नेता कॉ. रामकरण ने भी सभा को संबोधित किया।

निर्माण मजदूरों का जिला सम्मेलन संपन्न

रोहतक (हरियाणा) : सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

रोहतक (हरियाणा): एआईयूटीयूसी से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर-मजदूर यूनियन हरियाणा का रोहतक जिला सम्मेलन 22 अगस्त को स्थानीय छोटूराम पार्क में हुआ जिसमें जिला भर से भवन निर्माण मजदूर शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉ. राजकुमार, प्रधान जिला रोहतक ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव और एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉ. सत्यवान थे।

सम्मेलन में मांग की गई कि बोर्ड का आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए, पर्याप्त संख्या में स्टाफ भर्ती किया जाए। निर्माण कारीगर मजदूरों के पंजीकरण व हितलाभ पाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। पूरे साल काम का इन्तजाम हो। दिहाड़ी मारने वालों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज हो और उन्हें कड़ी सजा दी जाये। दिहाड़ी दिलाने के लिए सुनवाई और शिकायत के तुरंत निपटारे की व्यवस्था की जाए। बोर्ड से कन्यादान का लाभ पाने के लिए विवाह पंजीकरण की शर्त हटाई जाए। काम करने पर भी मालिक लिख कर नहीं देते हैं अत: उनके हस्ताक्षर करवाने की शर्त हटाई जाए। सभी हितलाभ आवेदन के एक महीने के अन्दर मिलने की गारन्टी हो। पंजीकरण के एक साल बाद हितलाभ देने की शर्त हटाई जाये। निर्माण श्रमिकों को बीपीएल के समान गुलाबी राशन कार्ड व सस्ता राशन दिया जाए। भविष्य निधि स्कीम लागू की जाए। काम के समय सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये जाएं, घायल होने या जटिल बीमारी में अस्पताल में भर्ती होने के दिन से लेकर पूर्णत: ठीक होने तक श्रमिक के इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करे और जब तक इलाज चले उसे मजदूरी दी जाए। कारीगर-मजदूरों को प्लाट खरीदने व मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये अनुदान दो। लेबर चौकों पर पीने के पानी, शौचालयों व शैडों की व्यवस्था करो और स्थायी रैन बसेरे बनाये जाएं। साइकिल की सहायता राशि बढ़ा कर 5000 रुपये की जाए। मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा कर कम से कम 18000 रुपये महीना किया जाए और साल में 365 दिन काम दिया जाये। सभी पंजीकृत कारीगर-मजदूरों के स्वास्थ्य कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी किये जायें।

अंत में एक जिला कमेटी का गठन किया गया जिसके जिला प्रधान कॉ. राजकुमार समचाना और सचिव कॉ. केशु काहनौर चुने गए।

शोषण के विरुद्ध पीतल मजदूरों ने निकाला जुलूस

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : पीतल मजदूर यूनियन ने पीतल मजदूरों की उपेक्षा के विरोध में 29 अगस्त को जीआईसी और सुभाष पार्क, दिल्ली रोड से जुलूस निकाले। ये कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गए।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पीतल मजदूरों को श्रम कानून के अनुसार न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उनका शोषण हो रहा है। इस प्रदर्शन में कॉ. विजय पाल सिंह, सुरेश पाल सिंह, नसीम वारसी, सतीश बिश्नोई, इस्लाम अली,

मुरादाबाद (उ.प्र.) : शोषण के खिलाफ रोष जुलूस निकालते हुए पीतल मजदूर

राम किशन मिश्रा, अमरजीत आदि शामिल रहे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सड़कों पर उतरीं

नारनौल (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी व हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 11 नवंबर को यहां सचिवालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम, नारनौल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा। इससे पहले हुई सभा का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की जिला सचिव स्वीटी देवी ने किया। यूनियन की जिला प्रधान कृष्णा देवी ने कहा कि ज्ञापन में प्रमुख मांगें हैं : मार्च 2018 में हुए समझौते के अनुसार जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सेवाकाल 10 साल से ज्यादा हो गया है उन्हें कुशल श्रमिक और जिनका 10 साल से कम से है उन्हें अर्ध कुशल श्रमिक का दर्जा प्रदान किया जाए, समझौते के अनुसार मानदेय की बजाय उनको वेतन दिया जाए और महंगाई सूचकांक से जोड़कर साल में दो बार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

ढलाई मजदूरों ने लंबी जदोजहद के बाद जीत ली जंग

समालखा (हरियाणा) : लम्बी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हजारों श्रमिक अपनी नौकरी बहाल कराने में सफल हुए और सालाना वेतन वृद्धि का अधिकार भी बचा लिया। उन्होंने वर्ष 2018 की वेतन वृद्धि भी प्राप्त कर ली।

फाऊन्डरी मालिकों ने 27 जून 2018 से इन श्रमिकों को काम से वंचित कर दिया था। इन पर शर्त रखी थी कि उन्हें काम तब मिलेगा जब वे यह आश्वासन लिखित रूप में देंगे कि आइन्दा वे अपना कोई भी जायज या वैधानिक अधिकार लागू करने की मांग नहीं उठाएंगे। इस नाजायज शर्त को मानने से श्रमिकों ने मना कर दिया। तभी से ढलाई उद्योग समालखा के हजारों श्रमिकों को काम से हटा दिया गया था। उन्होंने नौकरी पर बहाल करने की मांग की।

इस संघर्ष में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एआईयूटीयूसी व कारखाना मजदूर यूनियन समालखा ने खुलकर मजदूरों का साथ दिया। समय-समय पर उन्हें कानूनी सलाह व आन्दोलन के उतार-चढ़ाव से सम्बंधित जानकारी देते हुए श्रमिकों को उद्देश्य से भटकने से बचाया और सही रास्ता दिखाया। संघर्षरत श्रमिक एक पर एक बाधा का सामना करते हुए मालिकों की तमाम साजिशों व चालों को नाकाम करते रहे। फाऊन्डरी मालिक 70 दिनों तक लगातार ताबड़तोड़ प्रयासों के बावजूद एक भी श्रमिक से अपनी मनचाही शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं करवा सके। आखिर फाऊन्डरी मालिक अपनी जिद छोड़ने पर बाध्य हुए। गैरकानूनी तौर पर काम से हटाए गए सभी मजदूरों को पुरानी सेवा शर्तों पर 5 सितम्बर 2018 से नौकरी पर रखना स्वीकार किया। वर्ष 2018 के वेतन में मोल्डिग विभाग के कारीगरों व मोल्डरों को 13 रुपये प्रति दिहाड़ी, मजदूरों को 20 रुपये प्रति दिहाड़ी, नील वालों को 13 रुपये प्रति दिहाड़ी बढ़ा कर देना भी स्वीकार किया। तमाम तरह की बढ़ोतरी 1/7/2018 से देय मानी गई।

यह समझौता फाऊन्डरी मालिकों की एसोसिएशन व कारखाना मजदूरों की यूनियन के मध्य दो दिनों की लम्बी वार्ता के बाद सम्पन्न हुआ। मजदूरों का पक्ष एआईयूटीयूसी हरियाणा के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने रखा और उनके हितों की पैरवी की। कारखाना मजदूर यूनियन समालखा की तरफ से कॉमरेड महेन्द्र सिंह ने सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मजदूरों का साथ दिया।

बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन पर नौजवानों ने किया विरोध प्रदर्शन

रांची (झारखण्ड) : बेरोजगारी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर 11 सितंबर को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गनाइजेशन (एआईडीवाईओ) झारखंड राज्य द्वारा राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन रांची स्टेशन से प्रारंभ होकर बहू बाजार, कर्बला चौक, मेन रोड, कचहरी चौक होते हुए राजभवन के समक्ष एक सभा में तब्दील हो गया।

सभा को संबोधित करते हुए एआईडीवाईओ की अखिल भारतीय नेता एवं झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी सचिव कॉ. सुशांतो सरकार एवं अध्यक्ष कॉ. गीता शर्मा एवं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन झारखंड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. समर महतो ने विभिन्न समस्याओं पर अपनी बात रखी। सभा में सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से आये युवाओं ने शिरकत की।

केन्द्र व प्रदेश सरकारों की युवा विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ नौजवानों का पैदल मार्च

लखनऊ । ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) के तत्वावधान में 'सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दो अन्यथा जीवन जीने लायक बेरोज़गारी भत्ता दो', 'ख़ाली पड़े पदों पर अविलम्ब भर्ती करो', 'काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दो', तथा 'संविदा प्रथा को समाप्त कर सभी को स्थायी रोज़गार दो' सहित तमाम अन्य माँगों को लेकर तथा केन्द्र व प्रदेश सरकारों की युवा विरोधी-जन विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आये हज़ारों नौजवानों ने 6 सितम्बर को चारबाग़ रेलवे स्टेशन से ईको गार्डेन स्थित धरना स्थल तक 'पैदल मार्च' किया।

पैदल मार्च में युवा हाथों में माँग पट्टिकाएं लिए हुए नारे लगा रहे थे। धरना स्थल पर पहुँच कर मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. रविशंकर मौर्य ने व संचालन सचिव मण्डल सदस्य कॉ. रामकुमार यादव ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए एआईडीवाईओ की राष्ट्रीय महासचिव कॉ. प्रतिभा नायक ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा करने वाली मोदी सरकार नौकरी देने के बजाय हर महीने लगभग ढाई लाख की दर से पदों को ख़त्म कर रही है। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश की भाजपा-नीत सरकारों को घोर युवा विरोधी-जन विरोधी क़रार दिया।

एआईडीवाईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. जुबेर रब्बानी ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकारें सभी सरकारी विभागों को निजीकरण के हवाले करके पूँजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े का द्वार खोल रही हैं जिसके चलते नौकरियों के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए हमें सरकार के इस जनविरोधी क़दम के ख़िलाफ़ मज़बूती से लड़ना होगा। उन्होंने संविदा प्रथा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि स्थायी रोज़गार देने के बजाय युवाओं के जीवन में अनिश्चितता का माहौल बनाया जा रहा है।

अध्यक्षीय सम्बोधन में एआईडीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. रविशंकर मौर्य ने कहा कि युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए नशाख़ोरी, शराब, अश्लीलता के प्रचार-प्रसार में भाजपा-नीत सरकारें बढ़ावा दे रही हैं और झूठ, नफ़रत व भय का माहौल बनाकर युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से केन्द्र व प्रदेश की युवा-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ करने का आह्वान किया।

सभा को संगठन के प्रदेश सचिव कॉ. मकरध्वज, दिनेशकांत मौर्य, कमलेश मौर्य, राम कुमार यादव, जयप्रकाश, इन्दू शुक्ला आदि लोगों ने भी सम्बोधित किया।

अन्त में एक प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय प्रधानमंत्री को सम्बोधित एक चार सूत्री माँग पत्र माननीय राज्यपाल को सौंपा।

सभी बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दो — एआईडीवाईओ ने यह आवाज बुलंद की

भोपाल : बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए युवा

भोपाल : सभी सरकारी विभागों में लाखों खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करने, भयंकर बढ़ती बेरोजगारी की समस्या हल करने व सभी को रोजगार की मांग पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की मध्य प्रदेश राज्य समिति द्वारा गत दिनों यहां राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आये युवक-युवतियां स्थानीय नीलम पार्क में एकत्रित हुए।

सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करो, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दो, बेरोजगार नौजवानों को जब तक रोजगार ना मिले तब तक जीवन जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दो, संविदा एवं ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर स्थाई रोजगार दो – इन चार मांगों पर पूरे देश भर में एआईडीवाईओ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। युवा संगठन की मध्य प्रदेश राज्य समिति के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम हजारों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश राज्यपाल को सौंपा गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता एआईडीवाईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. जुबेर रब्बानी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 माह में 30 लाख से अधिक रोजगार खत्म कर दिए गए जबकि प्रधानमंत्री द्वारा हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। देशभर में सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। डीवाईओ ने मांग की कि राज्य व केंद्र सरकार अभिलंब रिक्त पदों पर स्थाई भर्ती करे।

डीवाईओ के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. लोकेश शर्मा ने कहा कि अभी हाल ही में चुनाव के पहले शिक्षकों की भर्ती होने की घोषणा की थी वह भी बहुत कम संख्या में जबकि मध्य प्रदेश में एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं उसमें भी वर्तमान अध्ययनरत बी. एड, डी.एड, डी.इल.इएड छात्र-छात्राओं के आवेदन पर रोक लगाई गई है। युवा संगठन डीवाईओ ने मांग की कि सभी बी.एड, डी.एड और डी एल एड में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में शामिल किया जाए। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बी. एड. डी.एड. छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए।

प्रदेश भर से आए युवा नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया। मंच संचालन राज्य सचिव कॉ. प्रमोद नामदेव ने किया। भोपाल, गुना, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, धार, रायसेन व अन्य जिलों की प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

शिक्षा बचाओ सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली : ग्रेडेड ऑटोनोमी, हेफा, एच.ई.सी.आई., इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनेन्स जैसे उन 'शैक्षणिक सुधारों' पर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा 24 अगस्त को गांधी शांति प्रतिष्ठान में शिक्षा सम्मेलन किया गया जिसमें छात्रों व अन्य शिक्षाप्रेमी लोगों ने शिरकत की। इस सम्मेलन को डॉ. नरेन्द्र शर्मा (अध्यक्ष, ऑल इण्डिया सेव एजूकेशन कमेटी, दिल्ली), डॉ. नंदिता नारायण (पूर्व अध्यक्ष, डूटा), डॉ. सुधीर सूथार (सचिव, जे.एन.यू.टी.ए.), डॉ. माजिद जमिल (सचिव, जे.टी.ए.), डॉ. रुकमणी सेन (एसोसिएट प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय), डॉ. गोपाल प्रधान (प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय), डॉ. पूनम भूषण (एसोसिएट प्रोफेसर, इग्नू), डॉ. श्रीनिवास बुर्रा (फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़, साउथ एसियन यूनिवर्सिटी), डा. ॅक्विनी प्रधान (प्रोफेसर, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय), डॉ. सुधांशु भूषण (प्रोफेसर, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा), डॉ. विनय कुमार (संयोजक, ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी, दिल्ली), कॉ. कमल साँई (अखिल भारतीय अध्यक्ष, ए.आई.डी.एस.ओ.) व का. अशोक मिश्र (महासचिव, एआईडीएसओ) ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते फासीवादी केन्द्रीकरण व शिक्षण संस्थानों में खत्म किए जा रहे जनवादी ताने-बाने के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। यू.जी.सी. को खत्म कर एच.ई.सी.आई. गठित करने का फैसला इसी दिशा में लिया गया कदम है। हेफा के तहत अब शिक्षण संस्थानों को सरकारी बजट के बजाय लोन के भरोसे चलना होगा। शिक्षा पर बजट को लगातार कम किया जा रहा है जो अब मात्र 3.48% रह गया है जबकि एजूकेशन सेस को हेल्थ व एजूकेशन सेस में तब्दील कर इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ग्रेडेड ऑटोनोमी के तहत शिक्षण संस्थानों को 'स्वायत्तता' प्रदान कर पूंजीवादी बाजार के निष्ठुर नियम के तहत शिक्षण संस्थानों को भी संचालित होने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

वक्ताओं ने उपस्थित छात्रों, शिक्षकों व देश की शिक्षाप्रेमी जनता से शिक्षा पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की तथा एक जुझारू प्रतिरोध आंदोलन गठित करने के लिए आगे आने की अपील की ताकि देश में एक सही मायने में वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष व जनवादी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जा सके तथा शिक्षा व समाज को बचाया जा सके।

आंगनवाड़ी कर्मियों व आशा श्रमिकों के क्रमशः मानदेय व प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की

प्रधान मंत्री की घोषणा पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशा श्रमिकों के क्रमशः मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की प्रधान मंत्री की घोषणा पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया में निम्नानुसार कहा है:

देश भर में आंगनवाड़ी कर्मियों और आशाओं के वर्षों से जारी सतत और दीर्घकालिक आंदोलन ने जब संसद के चुनाव दरवाजे दस्तक दे रहे हैं, तब प्रधान मंत्री को सत्ता में आने के चार साल बाद अपना मुंह खोलने को मजबूर कर दिया है।

आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के लिए मानदेय में क्रमशः 1500 और 750 रुपये बढ़ाने की और साथ ही साथ आशा श्रमिकों के प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा की गई जो कि उनके लिए उपलब्ध कार्यों के आइटम पर आधारित है जो निश्चित मासिक पारिश्रमिक की अनुपस्थिति में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है, यह उससे काफी कम है जिसकी वे वास्तव में हकदार थी। बीजेपी शासन के दौरान पहली बार यह जो वृद्धि हुई है, उसे आवश्यक वस्तुओं की आकाश-छूती महंगाई के कारण उनके पारिश्रमिक की खरीद क्षमता के अबाधित क्षरण के ऐवज में केवल क्षतिपूर्ति या मुआवजा ही कहा जा सकता है।

इस परिस्थितियों में हम उन योजनाओं में लगी हुई लाखों कामकाजी महिलाओं से आह्वान करते हैं कि अपनी एकता को कमजोर न पड़ने दें, बल्कि और भी मजबूत करें, स्कीम श्रमिकों की सभी श्रेणियां को लेकर, जिनमें मिड-डे मील श्रमिक भी शामिल हैं जिन्हें इस मामूली वृद्धि से भी वंचित रखा गया है – एक व्यापक आधार पर एकजुटता कायम करें और जब तक सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, तब तक स्वयंसेवक के बजाय 'कामगार' के रूप में नियमित करने, न्यूनतम वेतन 18000 रु. प्रति माह देने, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने आदि लंबित मांगें मानने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए आगे बढ़ें।

राफेल घोटाला ....

(पृष्ठ 1 का शेष)

आर्किटेक्चर द्वारा सबसे बड़ा आर्डर हासिल किया गया है। यह राशि लगभग 21 हजार करोड़ है। अंबानी की रिलायंस एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर डेसॉल्ट कंपनी द्वारा डेसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस बनायी गयी है। स्वाभाविक तौर पर ही आरोप लगां है कि रिलायंस के पास विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है। यह कंपनी सिर्फ एक साल पहले इस सौदे के बारे में बात शुरू होने के बाद बनी थी। इसके बावजूद, 60 वर्ष का अनुभव रखने वाली सरकारी संस्था एचएएल को खारिज कर रिलांयंस को इस समझौते में क्यों शामिल किया गया?

यहीं क्रोनी कैपीटलिज्म का सवाल महत्वपूर्ण बनकर दिखाई दे रहा है। अन्यथा, इस समझौते में एचएएल को छोड़कर अंबानियों के अचानक घुस जाने का कारण क्या हो सकता है? गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान 'गुजरात मॉडल' में सबसे अधिक लाभ कमाने वालों में अंबानी, अडानी आदि घराने अन्यतम हैं। यह बात सर्वविदित है कि 2014 में बीजेपी के उदय के पीछे अंबानियों ने पानी की तरह पैसा बहाया था। पिछले चार वर्षों में, नरेंद्र मोदी वह ऋण नहीं चुका पाए थे। वहीं हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में देखने को मिला है कि देश के 1 प्रतिशत धनकुबेरों की सम्पत्ति पिछले एक साल में 20.9 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है, जो देश के वित्त वर्ष 2017-18 के कुल बजट के बराबर है। इन धनकुबेरों में अंबानी भाई पहली कतार में हैं। अर्थात् मोदी के राज में इनके लिए बेरोकटोक लूट का इंतजाम कर दिया गया है। उसी लूट का ताजा उदाहरण राफेल घोटाला है।

दो पूर्व भाजपा मंत्रियों, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ-साथ प्रशांत भूषण आदि ने इस समझौते में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरेआम सवाल उठाया और कहा कि प्रधान मंत्री ने पिछली सरकार के समझौते को बदलने से पहले कैबिनेट की सुरक्षा विषयक समिति, रक्षा मंत्रालय, विदेश मामलों के मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख से कोई चर्चा नहीं की थी। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था। आरोप लगाए गए हैं कि अंबानी की कंपनी को यह डील प्राप्त करने के लिए इन रीति-नीतियों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने तीन महीनों में सीएजी की फोरेन्सिक लेखा परीक्षा कराने की मांग की। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें भारत सरकार ने जिस कंपनी से डील करने को कहा, उसी से डील करनी पड़ी।

सरकार के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है। प्रधान मंत्री हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि रक्षा समझौते को गुप्त रखने का फैसला किया गया है। यह निर्णय हो ही सकता है कि यह विमान सेना के लिए है इसलिए इसके तकनीकी मुद्दों को गुप्त रखना चाहिए। हालांकि यह ज्ञात है कि कंपनी न केवल इस विमान को भारत में बेच रही है, बल्कि उसने उसी विमान को दूसरे देशों में भी बेचा है। नतीजतन, तकनीकी गोपनीयता का मामला दबा-छुपा नहीं रहता है। लेकिन मूल्य का मामला या रिलायंस कंपनी के इस सौदे में शामिल होने का मुद्दा कोई गोपनीयता का मामला नहीं है। तब फिर यह देश के लोगों से क्यों छुपाया जा रहा है? विमान खरीदने की यह भारी लागत मोदी सरकार द्वारा लोगों से वसूले हुए टैक्सों से ही दी जाएगी। तब तो सरकार द्वारा लोगों को तथ्य बताये जाने अनिवार्य हैं। सरकार को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने खुलासा करना चाहिए कि यह सौदा तीन गुना ज्यादा क्यों है, सरकार की संस्था एचएएल को छोड़कर बिना कोई पूर्व अनुभव के रिलायंस को इस समझौते में शामिल क्यों किया गया है? इसके कारण उन्हें कितना मुनाफा मिलेगा?

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो सभी मामलों में पारदर्शिता की बात करते हैं, देश के हितों की रक्षा की बात कहते हैं। तब फिर वे इस तरह के गंभीर मामले की पारदर्शिता की रक्षा के लिए इतने अनिच्छुक क्यों हैं? क्या बीजेपी के लिए अंबानी का हित ही देश हित हो गया है? प्रधान मंत्री निश्चय ही बोफोर्स घोटाले की बात नहीं भूले होंगे। जो कांग्रेस ईमानदारी का तमगा लगाकर अचानक इतना इतराने लगी है, क्या वह भूल गई कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ही तो उसे पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने ठुकरा दिया था, उसी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान मंत्री के खिलाफ बोफोर्स कंपनी से रिश्वत में 64 करोड़ रुपये का कमीशन लेने का आरोप लगा था। आरोप का कोई जवाब नहीं दे सकने पर कांग्रेस सरकार गिर गई थी। बीजेपी नेताओं को राफेल घोटाले के आरोपों का भी उचित जवाब देश के लोगों को देना होगा। फिलहाल सरकार ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। देश की जनता को देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।

वोटों के स्वार्थ में बदला मुगलसराय स्टेशन का नाम

प्रस्ताव और योजनाएं पहले ही कर दी गई थीं, बाकी को लागू किया गया था। यह 5 अगस्त को पूरा हो गया था। इस दिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल दिया। स्टेशन का नया नाम आरएसएस नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया।

1883 में, जब गुलाम भारत में यह महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन बनाया गया था, उस समय छोटे से इस शहर का नाम मुगलचक या मुगलसराय रखा गया था। पता लगा है कि मुगलों के राज में बादशाह हुमायूं की फौज ने बंगाल के सूबेदार शेर शाह सूरी की फौज को बिहार की तरफ खदेड़ते हुए यहां पर डेरा डाला था। उस समय से, मुगलसराय का नाम लोगों की जबान पर चढ़ गया था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद स्वाभाविक रूप से यही नाम मान लिया गया। बीजेपी सरकार ने अचानक 135 साल के इतिहास को बदलने का कदम उठाया है। फरवरी 1968 में मुगलसराय स्टेशन के पास दीनदयाल उपाध्याय मृत पाए गए थे। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने स्टेशन का नामकरण उनके नाम पर करने का फैसला लिया है।

किसी भी स्थान, प्रतिष्ठान, सड़क, स्टेशन इत्यादि का नाम बदला जा सकता है। जब आप किसी व्यक्ति के नाम पर नया नामकरण करते हैं तो विचारणीय बात क्या होनी चाहिए? इस मामले में, अवश्य ही यह विवेचना की जानी चाहिए कि समाज-सभ्यता की प्रगति में उनकी भूमिका क्या रही है। निष्पक्ष दृष्टिकोण में, उनकी ऐतिहासिक स्थिति और जन मानस में उनके स्थान की भी समीक्षा की जानी चाहिए। इस मामले में, किस पैमाने से बीजेपी ने फैसला किया है, इसको लेकर सवाल उठा है।

ये दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? जिस आरएसएस ने देश में राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के लिए जनसंघ पार्टी बनाई थी, जिसका नाम बदल कर अब भाजपा हो गया है, वे उसके अध्यक्ष थे। एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में, वे साम्राज्यवाद-विरोधी मुक्ति आंदोलन के खिलाफ थे। आरएसएस विचारधारा से प्रेरित लोगों का कहना यह था कि जो लोग अपने दिल में हिंदुत्व का गौरव वहन नहीं करते हैं, वे देश के दुश्मन हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदू धर्म और सांप्रदायिक मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करने के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के विरोध में भी काम किया है। इसी हीन प्रतिक्रियावादी चिंतन के धारक-वाहक के नाम पर स्टेशन का नाम रखने का उद्देश्य महज यही हो सकता है – हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उन्हें पेश करना। इतिहास के सही गतिपथ पर जो मुगलसराय नाम आया है, उसे मिटाकर एक प्रगतिविरोधी व्यक्ति के नाम को दलगत स्वार्थ में जनता पर थोप देना। यह भी तो एक प्रकार से इतिहास की तोड़ मरोड़ है! बीजेपी इतिहास में लोकतांत्रिक नेता की कमी को इसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रही है। वे कहीं वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति स्थापित करके, कहीं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर स्टेशन का नामकरण करके देश के इतिहास में खुद को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। वे जोर जबरदस्ती से अपनी उत्कृष्टता साबित करना चाहते हैं।

बीजेपी सरकार के चार साल के शासन में देश का आर्थिक शोषण-उत्पीड़न विकराल रूप लेता जा रहा है। टैक्सों और महंगाई की मार बेलगाम बढ़ती जा रही हैं। 'अच्छे दिन', 'सबका साथ सबका विकास', 'मेक इन इण्डिया' जैसे रोजाना लगाये जाने वाले नारों की एक-एक करके पोल खुलती जा रही है। इस स्थिति में, लोगों को गुमराह करके वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए उन्हें हिंदुत्व का पुराना एजेण्डा ही बस्ते से निकालना पड़ रहा है। उसी तरह राज्यों में धर्मान्धता, सांप्रदायिक फूट और धार्मिक अशांति फैलाने का एक कट्टरपंथीकरण चल रहा है। इतिहास को भुला देने के लिए वे कह रहे हैं कि ऐतिहासिक ताजमहल नहीं ये तो हिंदू मंदिर तेजोमहल है। अम्बेडकर की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। शिक्षा के आंगन में, पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म के कर्मकाण्ड को अनिवार्य बताया जा रहा है। कभी नमाज पढ़ना बंद करने का फतवा जारी किया जा रहा है और गोहत्या बंद कर मुस्लिम जनता को आतंकित करके रखा जा रहा है। मुगलसराय के नाम का परिवर्तन भी इसी धारा से आया है। यह वोट सर्वस्व दिवालिया राजनीति के स्वार्थ में बीजेपी के एक और हथकण्डे का उदाहरण है।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication : November 20, 2018

इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में एआईयूटीयूसी और एआईपीएफ ने की शिरकत

दुनिया भर में ऊर्जा उद्योग श्रमिकों का संयुक्त, जुझारू मजदूर आंदोलन गठित करने का आह्वान

तिरुवनथपुरम (केरल) : वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (डब्लूएफटीयू) द्वारा 11-12 सितंबर को यहां ऊर्जा उद्योग श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आयोजित की गई। सभी महाद्वीपों को कवर करते हुए 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 152 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। डब्लूएफटीयू से संबद्ध ट्रेड यूनियन के रूप में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) ने भी कांग्रेस में हिस्सा लिया। एआईयूटीयूसी के अखिल भारतीय सचिवमण्डल के सदस्य कॉमरेड शंकर दासगुप्त और एआईयूटीयूसी से संबद्ध अखिल भारतीय पावरमेन फेडरेशन (एआईपीएफ) के महासचिव कॉमरेड समर सिन्हा इस कांग्रेस में उपस्थित थे। भारत से डब्लूएफटीयू से संबद्ध ट्रेड यूनियनों के रूप में एआईटीयूसी और सीआईटीयू के प्रतिनिधियों ने भी इस कांग्रेस में भाग लिया।

कांग्रेस में विचार-विमर्श में हिस्सा लेते हुए एआईयूटीयूसी की तरफ से कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने कहा कि चूंकि ऊर्जा क्षेत्र पूरे विश्व में मानव समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए सभी संकटग्रस्त साम्राज्यवादी देशों का शासक पूंजीपति वर्ग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व कायम करने के लिए गलाकाट होड़ में है। खासकर समाजवादी खेमे के दुर्भाग्यपूर्ण पतन के बाद दुनिया भर में तेल संपत्तियों को हथियाने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी और उसके सहयोगी देशों के खुलेआम आक्रमण और हस्तक्षेप तेल उत्पादों में समृद्ध देशों पर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के मार्ग पर चलते हुए भारत में एक पर एक आई सरकारों ने इस आवश्यक क्षेत्र में अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कॉर्पोरेट घरानों के लिए ऊर्जा क्षेत्र खोल दिया है। कॉरपोरेट घरानों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण और वर्चस्व बढ़ते जाने के परिणामस्वरूप भारत सहित पूरी दुनिया में पूंजीपति वर्ग अपनी-अपनी सरकारों के जरिये मजदूरों के कष्टसाध्य अधिकारों का हनन करने वाले कठोर कानूनों को लागू कर रहा है। इस स्थिति में, कॉमरेड दासगुप्ता ने जोर देकर कहा कि एआईयूटीयूसी दृढ़ता से महसूस करता है कि मेहनतकश लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में बढ़ते हमले का मुकाबला करने के लिए दुनिया के आम लोगों और श्रमिकों के संयुक्त जुझारू प्रतिरोध आंदोलन गठित करना वक्त का तकाजा है।

अपने वक्तव्य का समाहार करते हुए कॉमरेड दासगुप्ता ने महान कार्ल मार्क्स द्वारा सिखाए गए वर्गोन्मुखी ट्रेड यूनियनों के मूल उद्देश्य को याद दिलाया कि वे 'साम्यवाद के स्कूल' हैं और इस मामले में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को अर्थवाद और सुधारवाद संकीर्ण सीमा से मुक्त किया जाए जो मजदूर वर्ग और अन्य शोषित लोगों के हित के लिए हानिकारक है। कॉमरेड समर सिन्हा ने विभिन्न देशों के टीयूआई (ऊर्जा) के प्रतिनिधियों से बातचीत की और दुनिया भर में ऊर्जा उद्योग के श्रमिकों के एकजुट आंदोलन पर जोर दिया।

समापन प्रस्ताव में, कांग्रेस ने सभी संबंधित श्रमिकों की साझी मांगों पर हड़ताल और प्रदर्शन का विश्व दिवस मनाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया और इस मामले में इसने पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों के बढ़ते हमलों के खिलाफ दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों की अपनी सभी संबद्ध ट्रेड यूनियनों और ट्रेड यूनियन इंटरनेशनलों(टीयूआई) से सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सभी श्रमिक यूनियनों की एकता और एकजुटता का निर्माण करने का आह्वान किया।

मी-टू मूवमेन्ट : **सीने में दबा हुआ दर्द छलक पड़ा**

बैंगलोर में सम्मेलन आयोजित

बैंगलोर : देश में 'मी-टू' आंदोलन की पृष्ठभूमि में महिलाओं की सुरक्षा और मान-मर्यादा की मांग करने वाले सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (सी) की कर्नाटक राज्य सचिव कॉमरेड के. उमा

'मी-टू' आन्दोलन के अंग के तौर पर एआईएसएसएम की पहल पर यूवीसीई एल्यूमनी एसोसिएशन हाल, बैंगलोर में 25 अक्टूबर को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। "मैं भी यौन-उत्पीड़न की शिकार हूं" यह एलान यौन-उत्पीड़न के खिलाफ यौन-उत्पीड़न की शिकार हुई असहाय महिलाओं का एक जोरदार विरोध है। कई कारणों से, जो यौन-उत्पीड़न के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल सकीं, 'मी-टू' आंदोलन से उनके मुंह से छलक उठा है वह दबा हुआ दर्द।

संगठन की राज्य सचिव कॉमरेड शोभा ने कहा कि दो साल पहले अमेरिका में एक काली औरत ने 'मी-टू' आंदोलन शुरू किया था। आज इसकी लहरें भारत में आ गई हैं। संगठन की कर्नाटक राज्य अध्यक्ष बी.आर. अर्पणा के शब्दों में, "इस आन्दोलन ने महिलाओं की अव्यक्त व्यथा-वेदना दब कर नहीं रह जाए, इसके लिए विरोध की आवाज बुलंद करने का मंच दे दिया है।" जानी-मानी कानूनविद, महिला आन्दोलन की कर्मठ कार्यकर्ता हेमलता महिषी ने कहा कि जो महिलाएं इस तरह सचेत हुई हैं, उनका साथ देना चाहिए। कर्नाटक के समाचार पत्र 'प्रजावनी' के कार्यकारी निदेशक रवींद्र भट्ट के शब्दों में कहें, तो इस आंदोलन में हर तबके की महिलाओं की भागीदारी की जरूरत है, विशेष रूप से मिल-कारखानों की कामकाजी महिलाओं को, जो कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की शिकार होती हैं। एआईएमएसएस की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. सुधा कामथ ने कहा कि यौन उत्पीड़न कैंसर की तरह फैल रहा है। सरकारी और निजी शैक्षिक संस्थानों, परिधान उद्योग, यहां तक कि कृषि में भी महिलाएं छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकार हैं।

एसयूसीआई (सी) की कर्नाटक राज्य सचिव कॉमरेड के. उमा ने कहा कि कार्यस्थलों पर 70 फीसद महिलाओं का यौन शोषण होता है। 'मी-टू' आंदोलन ने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जोरदार मांग बुलंद की है जिसे और भी ताकतवर करने की जरूरत है। यह आंदोलन पुरुष-विरोधी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए। नारी मुक्ति के लिए सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व से ही नहीं, बल्कि पूंजीवादी शोषण के जुए से भी महिलाओं को निजात दिलाने की जरूरत है, महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही शोषण के उन्मूलन के इस संघर्ष में आगे आना होगा।

9-10 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल को लेकर मजदूर कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय सम्मेलन

रोहतक (हरियाणा) : 9-10 जनवरी 2019 की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर तक मजदूर कर्मचारियों व आम जन में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। यह संकल्प यहां 11 नवंबर को कर्मचारी भवन में आयोजित हरियाणा की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में लिया गया। सम्मेलन में राज्य भर से सैकड़ों यूनियन प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। सम्मेलन के दौरान मौजूद नेताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में बेचने, बड़े कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपय की छूट देने और मजदूर-कर्मचारियों के बड़े आंदोलनों के दम पर हासिल किए गए श्रम अधिकारों के हनन करने के खिलाफ देशव्यापी 2 दिन की हड़ताल होने जा रही है। भाजपा सरकार की मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों से जनता में भारी रोष व्याप्त है।

सम्मेलन के संचालन के लिए बने अध्यक्ष मंडल में एआईयूटीयूसी की तरफ से कामरेड हरि प्रकाश के अलावा अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों के नेतागण धर्मवीर लोहान, अनिल कुमार, सतवीर सिंह, जग रोशन, आरके नगर, संजय कुमार आदि शामिल थे।

सम्मेलन को एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कामरेड ईश्वर सिंह राठी, एटक के महासचिव बेचू गिरी, सीटू के महासचिव जय भगवान, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव सूबे सिंह, सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा, हरियाणा बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के चेयरमैन एन.पी. मुंझाल ने प्रमुख रूप से संबोधित किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503